



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2011/श्रावण 13, 1933

No. 439]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2011/SRAVANA 13, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 600(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुरानाठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंजाब राज्य में प्रवृत्त, पंजाब विलासिता कर अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

## उपांतरण

1. संपूर्ण अधिनियम में, “राज्य सरकार” शब्द जहां कहीं भी आते हैं के स्थान पर, “प्रशासक” शब्द रखे जाएंगे ।
2. धारा 1 में, उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—  
“1(क) ये संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित होंगा ।”
3. धारा 2 के, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(क) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;  
(कक) “निर्धारण प्राधिकारी” से इस अधिनियम के अधीन प्रशासक द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारण करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।”
4. धारा 3 की, उप-धारा (2) में, “पंजाब राज्य” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे ।
5. धारा 18 की, “पंजाब राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित” शब्दों का लोप किया जाएगा ।
6. धारा 41 की, उप-धारा (1) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में, “पंजाब” शब्द के स्थान पर “चंडीगढ़” शब्द रखा जाएगा ।
7. धारा 47 में, उप-धारा (3) में,—  
(क) “राज्य विधान सदन” शब्दों के स्थान पर, “संसद् के प्रत्येक सदन” शब्द रखे जाएंगे ।  
(ख) “दस दिन” शब्दों के स्थान पर “तीस दिन” शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 48 की, उपधारा (2) में, “राज्य विधान सदन” शब्दों के स्थान पर “संसद् के प्रत्येक सदन” शब्द रखे जाएंगे ।

9. धारा 49 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. यू-11020/3/2010-यूटीएल]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

### उपाबंध

पंजाब विलासिता कर अधिनियम, 2009  
(2009 का पंजाब अधिनियम सं0 4)

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का नाम पंजाब विलासिता कर अधिनियम, 2009 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होगा ।

### अध्याय-1

#### प्रारंभ

परिभाषाएं ।

(क) “निर्धारण प्राधिकारी” से इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) “प्रीतिभोज हाल” से कोई परिसर, बाग या फार्म हाउस, विवाह स्थान या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, जहां किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए ठहरने या स्थान को विवाह, स्वागत समारोह, अभिसमय, प्रीतिभोज, किट्टी पार्टी, बैठक या माल की बिक्री के लिए प्रदर्शनी या चाहे वे नियमित या आवधिक या अनियमित आधार पर समारोह या महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यवस्था करने के लिए किराए पर दिया जाता है ;

(ग) “प्रीतिभोज हाल में विलासिता उपलब्ध कराने के लिए प्रभार” जिसे अंतर्गत जो दान या खैरात या प्रीतिभोज हाल में विलासिता उपलब्ध कराने के लिए किसी भी नाम से जानी गई से प्राप्त की गई कोई रकम भी है;

(घ) “आयुक्त” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ.) “रियायत दर” स्वत्वधारी द्वारा विलासिता के लिए नियत, सामान्य दर से निम्न कोई दर अभिप्रेत है;

(च) “होटल” से कोई परिसर, जिसके अंतर्गत लान, वासा घर, क्लब, यदि कोई हो, या अवकाश समागम भी है, अभिप्रेत है, जहां किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए यदि नियमित या अत्यकालिक या यदा कदा आधार पर किराए पर दिया जाता है ;

(छ) “विलासिता” से उपभोग, सुखद या भोग के प्रयोजन के लिए दी गई सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(ज) “प्रीतिभोज हाल में विलासिता उपलब्ध कराना” से राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विलासिता के रूप में किसी राशि के संदाय पर जो कि प्रत्येक अवसर के लिए पांच हजार रुपए से कम का न हो या ऐसी अन्य राशि जो की विनिर्दिष्ट की जाए, पर प्रीतिभोज हाल में वास सुविधा या स्थान के रूप में उपलब्ध कराने से अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत वायुशीतलन, वातानुकूलन, कुर्सियां, मेजे, लिनेन, बर्टन और जलयान, शमियाना, टैंट, मंडप, विद्युत, जल, इंधन, आंतरिक या बाह्य सजावट, संगीत वाद्य-मंडल, सीधा प्रसारण या अन्य इसी प्रकार की सुख-सुविधाएं भी हैं चाहे यदि ऐसे प्रभार सम्मिलित रूप से या पृथक्-पृथक् लिए गए हों किंतु इसके अंतर्गत खाद्य और पेय के लिए गए प्रभार सम्मिलित नहीं हैं ;

**रप्टीकरण :-** पांच हजार रुपए की राशि या किसी अन्य विनिर्दिष्ट राशि की गणना करते समय, उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभार को सम्मिलित रूप से हिसाब में लिया जाएगा यदि वास सुविधा के लिए कोई प्रभार स्वत्वधारी द्वारा या उसको निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पृथक् से प्राप्त किया गया हो ।

(झ) “होटल में विलासिता उपलब्ध कराना” से राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विलासिता के रूप में किसी राशि के संदाय पर जो कि प्रति दिन दो सौ रुपए से कम का न हो, होटल में वासा के लिए वास सुविधा के रूप में उपलब्ध कराने से अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत वातानुकूलन, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो संगीत, हैत्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, तरणताल, सम्मेलन कक्ष या अन्य इसी प्रकार की सुख सुविधाएं भी हैं चाहे ऐसे प्रभार सम्मिलित रूप से या पृथक् पृथक् लिए गए हों किंतु इसके अंतर्गत खाद्य और पेय के लिए गए प्रभार सम्मिलित नहीं हैं ;

**रप्टीकरण :-** दो सौ रुपए की राशि या किसी अन्य विनिर्दिष्ट राशि की गणना करते समय, उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभार को सामूहिक रूप से हिसाब में लिया जाएगा यदि सुख सुविधा के लिए कोई प्रभार स्वत्वधारी द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो ।

(ज) “सामान्य दर” से ऐसी दर अभिप्रेत है जो किसी होटल या प्रीतिभोज हाल में सामान्य व्यवहार में छूट देने के पश्चात् किसी प्रयोगकर्ता से प्रभारित की गई है, किंतु नकद छूट यदि कोई हो, इसमें सम्मिलित नहीं है ;

(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित नियम अभिप्रेत है

(ठ) “स्वत्वधारी” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी या ठेकेदार या पट्टेदार, यथास्थिति किसी भी हैसियत में, होटल या प्रीतिभोज हाल का प्रबंध करता है और जिसके अंतर्गत व्यक्ति भी है, जो तत्समय ऐसे होटल या प्रतिभोज हाल के कार्य प्रबंध कर रहा है ;

(ड) “धारा” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ढ) “राज्य सरकार” से पंजाब राज्य सरकार के उत्पाद-शुल्क और कराधान विभाग अभिप्रेत है ;

(ण) “कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित और संग्रहित विलासिता कर अभिप्रेत है ; और

(त) “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

आयुक्त और अन्य अधिकारी।

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उसे ऐसे अन्य अधिकारी सहायता करेंगे जो समुचित समझे जाएं।

(2) आयुक्त की अधिकारिता संपूर्ण पंजाब राज्य पर होगी और उसे प्रदत्त या अधिरोपित इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए सभी अन्य अधिकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए आयुक्त की सहायता करेंगे, और अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

## अध्याय -2

### होटल और प्रीतिभोज हाल में विलासिता उपलब्ध कराने पर कर का उद्ग्रहण

होटल पर कर का उद्ग्रहण।

4. (1) प्रत्येक स्वत्वधारी, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी दर पर होटल में प्रतिदिन आधार पर उपलब्ध कराई गई विलासिता के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम पर, इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने का दायी होगा किंतु ऐसा कर कुल प्राप्त रकम का पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) प्रतिदिन आधार से भिन्न की दशा में, होटल में उपलब्ध कराई गई विलासिता के लिए स्वत्वधारी द्वारा कोई रकम प्राप्त की गई है पर कर के दायित्व को अवधारित करने में दैनिक औसत प्रभार के मद्द प्राप्त को विचार में लिया जाएगा:

परंतु केवल तभी कर उद्ग्रहीत होगा, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट दो सौ रुपए प्रतिदिन के अधीन या ऐसी अन्य राशि विलासिता के लिए प्रभारित करे।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उद्ग्रहीत कर स्वत्वधारी द्वारा ऐसी शीति से संदत्त होगी, को विहित की जाए।

5. (1) प्रत्येक स्वत्वधारी, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी दर पर प्रीतिभोज हाल में प्रतिदिन के आधार पर उपलब्ध कराई गई विलासिता के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम पर, इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने का दायी होगा, किंतु ऐसा कर कुल प्राप्त रकम का पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परंतु केवल तभी कर उद्ग्रहीत होगा, यदि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, पांच हजार रुपए प्रतिदिन या ऐसी अन्य राशि विलासिता के लिए प्रभारित करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर, स्वत्वधारी द्वारा ऐसी शीति से संदत्त होगा

जो विहित की जाए ।

कर की गणना की पद्धति ।

6. (1) जहां यथास्थिति किसी होटल या किसी प्रीतिभोज हाल में उपलब्ध कराई गई विलासिता के लिए प्रभार जिसमें खाद्य और पेय के लिए प्रभार सम्मिलित किए गए हैं, निर्धारण प्राधिकारी, स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पृथक् प्रभारों का पृथक्करण कर सकेगा, जैसे विलासिता के लिए प्रभार और खाद्य तथा पेय के लिए प्रभार ।

(2) जहां यथास्थिति, किसी होटल या किसी प्रीतिभोज हाल में उपलब्ध कराई गई विलासिता के लिए प्रभार से भिन्न कोई सेवा प्रभार, स्वत्वधारी द्वारा संग्रहित और या तो संपूर्ण या अंशतः विनियोजित की जाती है तथा कर्मचारिवृद्ध को संदत्त नहीं किया जाता है, ऐसे प्रभार को विलासिता के लिए प्रभार का भाग समझा जाएगा ।

(3) जहां यथास्थिति, किसी होटल या किसी प्रीतिभोज हाल में विलासिता किसी व्यक्ति को निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी विलासिता के लिए सामान्य दर पर कर उद्ग्रहित किया जाएगा ।

(4) जहां किसी होटल में कतिषय विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या को सामान्य दर पर विलासिता उपलब्ध कराई गई थी, किंतु वास्तव में वह विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से अधिक द्वारा उपभोग की गई है तब कर उसी दर पर अतिरिक्त व्यक्तियों पर कर उद्ग्रहित किया जाएगा ।

प्रभार की घोषणा ।

7. प्रत्येक स्वत्वधारी, यथाविनिर्दिष्ट, उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विलासिता के लिए सामान्य दर की घोषणा करेगा, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर कर संदेय करने का दायी होगा, जो विहित की जाए ।

### अध्याय -3

#### रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण ।

8. (1) स्वत्वधारी जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी है, किसी होटल या प्रीतिभोज हाल में विलासिता प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं होता है ।

(2) प्रत्येक स्वत्वधारी उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए जब ऐसा स्वत्वधारी इस अधिनियम के अधीन कर संदेय करने का दायी होता है, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी फीस और ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए ।

(3) यदि आयुक्त को समाधान हो जाता है कि उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन उचित रूप में है तो वह ऐसी रीति के अनुसार, स्वत्वधारी को रजिस्टर करेगा जो विहित की जाए और ऐसे प्रलूप में उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।

परंतु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियां सही नहीं हैं या अपूर्ण हैं या स्वत्वधारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित कोई साक्ष्य या सूचना, नहीं दी गई है तो वह जांच करने के पश्चात् और स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर देते हुए कारणों को अभिलिखित कर के आवेदन को रद् कर सकेगा । तथापि, आयुक्त द्वारा वांछित अपेक्षित सूचना देकर या संशोधित आवेदन देने के पश्चात्, स्वत्वधारी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में

रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन जमा कर सकेगा :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के लंबित होने के दौरान स्वत्वधारी, ऐसी रीति में कर की विवरणी फाइल करेगा और कर की देय रकम का संदाय करेगा ।

कारबार के परिवर्तन के संबंध में सूचना देना ।

9. यदि कोई स्वत्वधारी,-

(क) अपने कारबार को विक्रय या अन्यथा या कारबार के किसी स्थान का व्ययन करना ; या

(ख) अपने कारबार को बंद करता है, या अपने कारबार का अंतरित करता है या अपने कारबार के स्थान का परिवर्तन करता है या कारबार को किसी नए स्थान पर खोलना है ; या

(ग) अपने कारबार की के नाम, गठन या प्रकृति में परिवर्तन ; या

(घ) अभिकर्ता की नियुक्ति करता है ;

वह, इस संबंध में आयुक्त को ऐसी रीति में सूचना देगा जो विहित की जाए । किसी स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में, उसका विधिक प्रतिनिधि, ऐसी रीति में आयुक्त को सूचना देगा जो विहित की जाए :

परंतु यदि, यथास्थिति, कोई स्वत्वधारी या उसका विधिक प्रतिनिधि, परिवर्तन के संबंध में आयुक्त को सूचना देने में असफल रहता है तब, ऐसे परिवर्तन होते हुए भी, ऐसे स्वत्वधारी से देय कर वसूल किया जाएगा यदि उसने स्थान परिवर्तन नहीं किया है :

परंतु यह और कि कारबार के अंतरण की दशा में, यथास्थिति, अंतरिती या उसका उत्तराधिकारी इस अधिनियम के अधीन देय कर का संदाय करने का भी दायी होगा ।

10. आयुक्त धारा 9 के अधीन प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप, लिखित में आदेश द्वारा, संबंधित अभिलेख में आवश्यक परिवर्तन करेगा ।

11. (1) आयुक्त,-स्वत्वधारी द्वारा उसे रद्दकरण के किए गए आवेदन पर या स्वत्वधारी की निम्नलिखित अन्यथा जानकारी,-

(क) अपना कारबार बंद है ; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन देय कर का संदाय नहीं किया है ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है ; या

(ड) अपने रजिस्ट्रीकरण का दुरुपयोग करता है,

या अन्यथा सूचना पर, रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा ।

(2) स्वत्वधारी के किसी आवेदन से भिन्न उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण रद्द नहीं होगा ।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक स्वत्वधारी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर या किसी अन्य रकम के उचित और समय पर संदाय को प्रतिभूत करने के लिए पचास हजार रुपए की प्रतिभूति ऐसी रीति

रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन ।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

स्वत्वधारी से प्रतिभूति ।

में देगा, जो विहित की जाए ।

(2) आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति की निर्मुक्ति, उन्मोचन या प्रतिदाय के लिए स्वत्वधारी द्वारा उसको दिए गए किसी आवेदन पर संपूर्ण या उसके किसी भाग की निर्मुक्ति, उन्मोचन या प्रतिदाय का आदेश, यदि वह यह अपेक्षित नहीं है कर सकेगा ।

(3) जहां आयुक्त को, इस अधिनियम के अधीन संदेय योग्य कर की उचित वसूली के लिए किसी भी समय जब ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त है ऐसा करना समीचीन प्रतीत होता है, वह लिखित में आदेश द्वारा और कारण जो उसमें अभिलिखित किए जाएंगे स्वत्वधारी को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट दी जाएगी और विहित रीति में ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति, देने को अपेक्षा होगी, जो पहले से उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रतिभूति से अतिरिक्त ; उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परंतु किसी स्वत्वधारी से इस उपधारा के अधीन कोई अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं होगी जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता ।

(4) आयुक्त, किसी स्वत्वधारी द्वारा दी गई प्रतिभूति को नहीं रखेगा, यदि ऐसे स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जो और उसके विरुद्ध शोध्य शेष नहीं है ।

(5) आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय या प्रयोज्य कर या शास्ति की कोई रकम की वसूली के लिए किसी स्वत्वधारी द्वारा दी गई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति का संपूर्ण या उसके किसी भाग के द्वारा समवहत और समुचित पर्याप्त कारण के लिए लिखित में आदेश कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश स्वत्वधारी को सुनवाई को अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश के कारण प्रतिभूति अपर्याप्त ठहराए जाने की दशा में, स्वत्वधारी, रकम पूर्ण करने के लिए और प्रतिभूति देगा, जो कम हो गई थी जो ऐसी रीति में तथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा जो विहित की जाए ।

#### अध्याय 4

##### कर की विवरणी, निर्धारण, संदाय, वसूली और संग्रहण

कर का स्वनिर्धारण  
विवरणी और कर  
का संदाय

13.(1) प्रत्येक स्वत्वधारी इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर का स्वनिर्धारण करेगा और आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस संबंध में वर्ष के अवसान की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसे प्ररूप में विवरणी फाइल करेगा ।

(2) प्रत्येक स्वत्वधारी, विवरणी फाइल करने से पहले उसके द्वारा संदेय योग्य कर की पूरी रकम का संदाय करेगा और ऐसी रीति में ऐसे कर का संदाय का समाधानप्रद सबूत विवरणी के साथ देगा जो विहित की जाए । ऐसे सबूत के बिना कोई विवरणी को ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक विवरणी, ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित की जाए ।

(4) प्रत्येक स्वत्वधारी, मास के अवसान की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कर का संदाय मासिक रूप से करेगा और आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी विहित प्ररूप में इस संबंध में विवरण देगा । ऐसा विवरण देय कर की पूरी रकम का संदाय समाधानप्रद सबूत के साथ होगा । ऐसे संदाय के सबूत के बिना किसी विवरण को ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(5) यदि जहां किसी मास के लिए देय कर का संदाय करने में व्यतिक्रम होता है, उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित चाहे कोई विवरण दस दिन की अवधि से परे दिया गया है या नहीं दिया गया है तो व्यतिक्रमी स्वत्वधारी देय कर संदाय करने के अतिरिक्त ऐसे व्यतिक्रम तारीख से दो प्रतिशत की दर या उसके किसी भाग पर व्याज भी संदाय करेगा ।

(6) यदि स्वत्वधारी को, उसके द्वारा दी गई किसी विवरणी में कोई सद्भावी त्रुटि या लोप का पता चलता है तो वह ऐसी त्रुटि या लोप का पता के पश्चात् तुरंत संशोधित विवरणी फाइल द्वारा ऐसी त्रुटि या लोप को परिशोधित कर सकेगा । यदि ऐसी परिशुद्धि के परिणाम स्वरूप मूल विवरणी में दर्शित शोध्य कर से अधिक कर की रकम होती है, तो विलंब की अवधि के लिए प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से व्याज के साथ संदेय अधिक या अतिरिक्त कर की रकम के संदाय की रसीद उसके साथ उस रीति में संलग्न होगी जो विहित की जाए । वर्ष की तत्काल समाप्ति के पश्चात् तुरंत आने वाले वर्ष जिससे परिशुद्धि संबंधित है अनु या निर्धारण के लिए सूचना जारी करने के पश्चात् जो भी पूर्वतर हो ; अनुज्ञात होगा जहां ऐसी परिशुद्धि के परिणाम स्वरूप शोध्यकर की रकम के अधिकांश कर का संदाय कर दिया गया है, ऐसा अधिक रकम स्वत्वधारी के आवेदन पर ऐसी रीति से वापस की जाएगी, जो विहित की जाए ।

कर का निर्धारण ।

14. (1) जहां धारा 13 की उपधारा (1) या उपधारा (6) के अधीन किसी फाइल विवरणी की संवीक्षा पर स्वनिर्धारण पर किसी संदत्त कर या व्याज के समायोजन के पश्चात् कोई शोध्य कर या व्याज पाया जाता है, तो उपधारा (2) के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में स्वत्वधारी को प्रज्ञापना भेजी जाएगी जिसे मांग की सूचना समझा जाएगा, उपधारा (11) के अधीन तामील होंगी और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे :

परंतु स्वत्वधारी द्वारा किसी संदाय योग्य राशि या उसका कोई प्रतिदाय नहीं होने की दशा में विवरणी की अभिस्थीकृति प्रज्ञापना के रूप में जाएगी ;

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई प्रज्ञापना जिस वर्ष में विवरणी फाइल की जानी है के अवसान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अपने स्वयं के समावेदन पर या उसे प्राप्त सूचना के आधार पर, किसी स्वत्वधारी के उसके स्वयं के निर्णय द्वारा संदाय और उसके द्वारा कर संदाय का अवधारण कर केनिर्धारण बनाने के लिए कर सकेगा, जहां—

(क) स्वत्वधारी ने धारा 13 के अधीन विवरणी फाइल नहीं की है ; या

(ख) जहां विश्वास करने का यह निश्चित कारण है कि स्वत्वधारी द्वारा की गई विवरणी फाइल सही और पूर्ण नहीं है ; या

(ग) विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि स्वत्वधारी ने कर की देय रकम संदत्त नहीं की है ; या

(घ) अनंतिम विवरण दे दिया है ।

(3) आयुक्त, अपने स्वयं के समावेदन पर या उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर लिखित में आदेश द्वारा जो वह विनिर्दिष्ट करे ऐसी अवधि के लिए किसी स्वत्वधारी द्वारा संदेय कर की रकम का निर्धारण करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी को निर्देश कर सकेगा ।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई निर्धारण, यथास्थिति, तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर किया जा सकेगा, जब विवरणी फाइल की गई थी या फाइल करने के लिए शोध्य थी, जो भी पश्चात्तर्ती हो :

परंतु यह कि जहां परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, आयुक्त, लिखित में आदेश द्वारा तीन वर्ष के पश्चात् स्वत्वधारी के निर्धारण को अनुज्ञात कर सकेगा किंतु तारीख से छह वर्ष से कम न हो, जब विवरणी फाइल की गई थी या फाइल करने के लिए सम्यक् थी, जो भी पश्चात्तर्ती हो ।

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई निर्धारण, निर्धारण किया जाता है निर्धारण प्राधिकारी संबंधित स्वत्वधारी को नोटिस तामील करेगा और ऐसा नोटिस निम्नलिखित का कथन करेगा :-

(क) प्रस्तावित निर्धारण के लिए आधार ; और

(ख) आक्षेप फाइल करने के लिए समय, स्थान और शीति, यदि कोई हो ।

(6) निर्धारण प्राधिकारी उसे उपलब्ध कराए गए सभी संबंधित सामग्री को ध्यान में लेने के पश्चात् यथास्थिति, उपधारा (5) के अधीन या उसके पश्चात् तामील नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को करेगा और स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत ऐसे साक्ष्य को विचार में लेने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा ऐसे निर्धारण के आधार पर स्वत्वधारी को संदेय या प्रतिदेय की राशि के अवधारण के निर्धारण कर सकेगा ।

(7) निर्धारण प्राधिकारी, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से निर्धारण के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किए गए किसी निर्धारण को संशोधित कर सकेगा यदि उसे निम्नलिखित कारणों के लिए स्वत्वधारी द्वारा संदेय कर के निर्धारण के अधीन प्रकट करता है तो-

(क) ऐसे स्वत्वधारी ने कपट या जानबूझकर उपेक्षा की है ; या

(ख) ऐसे स्वत्वधारी ने दुर्व्यपदेशन किया है ;

(ग) राशि का कोई भाग किसी होटल या प्रीतिभोज हाल में प्रदान किए गए विलासिता लेखा पर प्राप्त किया है जो निर्धारण से बच गया था ।

(8) निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किए गए निर्धारण का परिशोधन कर सकेगा, यदि अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है कि उसे प्रकट करने में गलती की गई है ।

(9) कोई निर्धारण, उपधारा (7) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी आशयों और उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के अधीन किया गया निर्धारण होगा ।

(10) इस अधिनियम के अधीन लिया गया या तात्पर्यित कोई निर्धारण या अन्य प्रक्रियाओं का होना या इसके अधीन बनाए गए नियमों को निम्नलिखित नहीं किया जाएगा, -

(क) विहित प्रूप में वही नहीं था के कारण के लिए शून्य अभिखंडित या समझा जाएगा ; या

(ख) गलती, त्रुटि या उसमें लोप के कारणों द्वारा प्रभावित हुआ होगा :

परंतु इसके अधीन बनाए गए अधिनियम और नियमों के उपबंधों के साथ अनुरूपता

में सारभूत रूप से कोई ऐसा निर्धारण किया गया है।

(11) जब इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के परिणाम में कोई कर, ब्याज, शास्ति या अन्य कोई राशि संदेय की जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी संदेय करने को उसमें निर्दिष्ट राशि विहित प्रूप में एक मांग नोटिस स्वत्वधारी को तामील करेगा।

(12) इस धारा के अधीन संबंधित स्वत्वधारी को सुने जाने का अवसर दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अनंतिम निर्धारण ।

15. (1) धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, जहां अपवंचन की वृष्टि सहित कपट या जानबूझकर उपेक्षा की गई है या कर का संदाय करने से बचा है या स्वत्वधारी की ओर से देय कर संदत्त नहीं किया गया है या विवरणी फाइल नहीं की गई है तो निर्धारण प्राधिकारी कारणों के लिए लिखित में अभिलेख कर के अपवंचन, शून्य या असंदत्त कर का दायित्व कर के अवधारण की किसी अवधि के लिए अनंतिम निर्धारण कर सकेगा :

परंतु ऐसे स्वत्वधारी का कर दायित्व उसके द्वारा विहित रीति में अपनी विवरणी फाईल करने के पश्चात् अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा :

परंतु यह और कि स्वत्वधारी ऐसे अनंतिम निर्धारण में निर्धारित किए गए कर के अलावा भी ऐसे निर्धारित कर की रकम की दुगुनी शास्ति संदेय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनंतिम निर्धारण कपट या जानबूझकर उपेक्षा करने की पहचान की तारीख से छह मास की अवधि के अंदर किया जाएगा। तथापि आयुक्त, कारणों के लिए लिखित में अभिलेख कर के निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर और छह मास द्वारा उक्त अवधि का विस्तार कर सकेगा।

16. (1) यदि कोई स्वत्वधारी, इस अधिनियम के अधीन उस से देय कर की रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो वह कर की रकम के अतिरिक्त भी, अब तक संदाय की देय तारीख से प्रतिशत दो प्रतिशत की दर से कर ली उक्त रकम पर ब्याज संदेय करने का दायी होगा, वह ब्याज सहित ऐसे कर का वास्तव में संदेय करेगा।

(2) जब धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन पुनरीक्षित विवरण फाइल की गई हो, देय कर की रकम उच्चतर हो तब स्वत्वधारी अब तक की देय तारीख से ऐसे कर की रकम पर प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय करने का दायी होगा, वह ब्याज सहित ऐसे कर का वास्तव में संदेय करेगा।

(3) यदि कोई स्वत्वधारी विवरणी में कर की रकम की घोषणा करने में असफल रहता है अन्यथा जिसे घोषित किया जाना चाहिए था, ऐसे स्वत्वधारी अब तक कि देय तारीख से ऐसे कर की रकम पर प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय करने का दायी होगा, वास्तव में वह ऐसे कर की रकम का संदाय करेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति से कर की रकम या शास्ति देय है जो मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उसके द्वारा संदत्त नहीं किया गया है या यदि ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है, तो स्वत्वधारी कर की रकम या शास्ति के संदाय किए जाने के अतिरिक्त अब तक की देय कर की तारीख से प्रतिमास दो प्रतिशत की दर पर ऐसी रकम पर ब्याज संदेय करने का दायी होगा, वह वास्तव में ब्याज सहित, यथास्थिति, देय कर की रकम या शास्ति संदेय

करेगा :

परंतु यह कि जहां, कर या शास्ति की वसूली यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा रोक दी जाती है वहां कर की रकम या शास्ति रोक आदेश के पश्चात् बातिल होता है, रकम पर उपरोक्त दर पर व्याज सहित वसूल किया जाएगा। अंततः देय और ऐसे व्याज पाए जाते हैं तो कर या शास्ति जो भी पहले देय हो की तारीख से संदेय होगा।

(5) इस धारा के अधीन संदेय व्याज की रकम निम्नलिखित होगी,-

(क) पूरे मास के रूप में भास के किसी भाग को विचार में लेते हुए गणना होगी ;

(ख) संग्रहण और वसूली के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन समझी जाएगी ; और

(ग) शास्ति के अतिरिक्त, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाएगी।

स्पष्टीकरण,- इस धारा के प्रयोजन के लिए यदि स्वत्वधारी द्वारा कर का संदाय चैक द्वारा किया जाता है और बैंक द्वारा चैक अनादर हो जाता है तो इसे कर संदेय करने में स्वत्वधारी को असफल माना जाएगा।

17. इस अधिनियम के अधीन स्वत्वधारी द्वारा कर या कोई अन्य देय रकम या संदेय राज्य सरकार को ऋण देय होगा और उसे इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के रूप में संदत्त या वसूली की जाएगी।

18. किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, तत्समय प्रवृत्त, इस अधिनियम के अधीन स्वत्वधारी या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा संदेय कर की रकम, शास्ति, व्याज या कोई अन्य राशि जो रकम संदेय के लिए देय है पर तारीख से ऐसे स्वत्वधारी या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

19. इस अधिनियम के अधीन कोई कर की रकम, शास्ति, व्याज या कोई अन्य ऐसी देय राशि और संदेय के लिए है जो देय तारीख के पश्चात् असंदत्त है, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

20. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणाम को देय कोई रकम स्वत्वधारी द्वारा संदाय की जाती है तो सबसे पहले उसे समायोजित किया जाएगा, ऐसी रकम या उसके किसी भाग की वसूली के सिवाय, संदाय और उसके पश्चात् की तारीख पर उसके द्वारा संदेय व्याज के विरुद्ध शास्ति के रूप में देय रकम के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रोक दिया जाएगा। उसके पश्चात् बची हुई असमायोजित कोई रकम संदेय कर के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

21. (1) इस अधिनियम के अधीन स्वत्वधारी के विरुद्ध कोई वसूली कार्यवाही लंबित है, विक्रय, बंधक, उपहार, विनियम या अंतरण का अन्य प्रकार द्वारा कब्जा सहित जो भी कोई उसकी आस्ति हो शून्य या अपवर्चन कर, शास्ति, व्याज या कोई अन्य देय राशि या उसके विरुद्ध कोई देय होने वाला है आशय सहित उस पर या उसके भाग पर आशेप सृजित करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का अतिक्रमण में कोई प्रभार या अंतरण किया जाता है तो ऐसी कार्यवाही के समाप्त होने तक स्वत्वधारी द्वारा संदेय कर या कोई अन्य राशि से संबंधित कोई दावा शून्य करार दिया जाएगा :

राज्य सरकार को देय ऋण के रूप में कर।

दायित्व का इस अधिनियम के अधीन प्रथम प्रभार होना।

भूमि राजस्व के बकाया के रूप में असंदत्त रकम की वसूली।

किसी संदाय का समायोजन।

संपत्ति के अंतरण पर निवर्धन।

परंतु ऐसे प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होंगे, यदि यह आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से किए जाते हैं या ऐसे स्वत्वधारी से कर या कोई अन्य देय रकम का संदाय बैंक गारंटी के द्वारा पूर्ण सुरक्षित किया जाएगा। परादेय बकाया की दशा में, आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व को हिसाब में लेगा।

**स्पष्टीकरण-**इस धारा के प्रयोजन के लिए 'आस्ति' से भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, शेयर, प्रतिभूति और बैंक में नियतकालिक निक्षेप जिसको बढ़ाया जा सकता हो अभिप्रेत है जिसमें से उपरोक्त आस्तियां स्वत्वधारी के कारबार व्यापार में स्टाक के भाग के रूप में नहीं हैं।

## अध्याय 5

### प्रतिदाय

कर का प्रतिदाय।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, आयुक्त, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के अंदर, यथा विहित, स्वत्वधारी को कर, शास्ति या ब्याज की रकम का प्रतिदाय किया जाएगा, यदि कोई हो, उससे देय रकम के अधिक होने में ऐसे स्वत्वधारी द्वारा संदाय किया जाएगा। प्रतिदाय, या तो प्रतिदाय वाउचर द्वारा किया जा सकेगा या स्वत्वधारी के विकल्प पर प्रतिदाय समायोजन आदेश द्वारा किया जा सकेगा :

परंतु यह कि आयुक्त, कोई देय रकम की वसूली से ऐसी अधिक रकम को पहले लागू करेगा, जिसके संबंध में, धारा 14 की उपधारा (11) के अधीन मांग नोटिस तामील किया गया है या कोई अन्य रकम से जो कि देय है किंतु संदत्त नहीं की गई है और शेष रकम यदि कोई हो का प्रतिदाय किया जाएगा।

23. (1) जहां कोई रकम, आयुक्त द्वारा स्वत्वधारी को धारा 22 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए अपेक्षित है आगेदन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उसे प्रतिदाय नहीं की जाती है तो उक्त रकम पर आधा प्रतिशत प्रतिमास की दर पर साधारण ब्याज ऐसे स्वत्वधारी को प्रतिदाय देने की तारीख से साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान होने पर तुरंत तारीख से संदत्त किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण-** यदि उपर्युक्त साठ दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय करने में देरी होती है तो स्वत्वधारी का या तो पूर्ण या भाग में माना जाएगा तब ऐसी लंबित अवधि को संदाय के ब्याज के लिए अवधि से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) जहां अवधि के रूप में कोई प्रश्न उठता है जिसे उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के निर्बंधनों में अपवर्जित किया गया है तब ऐसे प्रश्न आयुक्त द्वारा अवधारित किए जाएंगे, और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(3) इस धारा के अधीन ब्याज एक पूर्णमास के उस मास के भाग को विचार में लेते हुए गणना की जाएगी।

24.(1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपील या और कार्यवाही या जहां कोई अन्य कार्यवाही के मामलों के अधीन उद्भूत प्रतिदाय देने के लिए कोई आदेश किया जाता है और सक्षम अधिकारी को राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रतिदाय करने के विचार से ऐसे प्रतिदाय किया जाएगा, ऐसे अधिकारी, आयुक्त की पूर्व अनुमति से प्रतिदाय को उस समय तक रोक सकेगा, जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित किया जा सके।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय को रोका जाता है, तो आयुक्त धारा 21

कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोकने की शक्ति।

के उपबंधों के अनुसार स्वत्वधारी के देय को अवधारित अंततः प्रतिदाय की रकम पर ऐसे अपील के परिणामस्वरूप या और कार्यवाही या अवधि के लिए कोई अन्य कार्यवाही, तारीख से प्रारंभ, आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के अवसान से तुरंत, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिदाय करने की तारीख को व्याज संदेय करेगा ।

## अध्याय 6

### लेखा का रखरखाव और निरीक्षण

लेखा का रखरखाव  
और रजिस्टर  
आदि ।

25. (1) प्रत्येक स्वत्वधारी, अपने कारबार से संबंधित लेखा का सही और पूर्ण रखरखाव करेगा और उसे रखेगा और ऐसे अन्य रजिस्टर या अभिलेख का भी अनुस्करण रखेगा, जो विहित किया जाए । ऐसे लेखे रजिस्टर या अभिलेख संबंधित वर्ष के पूर्ण होने के लिए उसके निर्धारण तक सुरक्षित अभिरक्षा में स्वत्वधारी द्वारा रखा जाएगा या जहां कोई अपील या पुनरीक्षण या ऐसे वर्ष से संबंधित में फाइल या सत्यापित की गई कोई अन्य कार्यवाही और जो लंबित है तो उसका निपटारा किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक स्वत्वधारी कर देय करने का दायी होगा जो प्रभार किसी होटल में वास सुविधा प्रदान करने के लिए प्राप्त करता है या प्रभार प्रीतिभोज कक्ष में प्रदान करने के लिए प्राप्त करता है, के संबंध में बिल या कैश मीमो जारी करेगा और उसमें ऐसे प्रभार की सही रकम, जिससे उसने प्राप्त किया है व्यक्ति का नाम और पता वर्णित करेगा । जहां ऐसे प्रभार किसी विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं तो उस मुद्रा का नाम ऐसे बिल या कैश मीमो में साफ तौर पर वर्णित किया जाएगा । ऐसे स्वत्वधारी द्वारा जारी कैश मीमो में, यथास्थिति, होटल या प्रतिभोज कक्ष का पूरा नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या दी जाएगी ।

निरीक्षण  
तालाशी  
शक्ति । और  
की

26. (1) आयुक्त या निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाए किसी स्वत्वधारी से अपने समक्ष जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो लेखों, रजिस्टर का अभिलेख, या अन्य दस्तावेज या उसके कारबार से संबंधित कोई अन्य सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) कोई होटल या प्रीतिभोज कक्ष के कारबार से संबंधित लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के सभी अभिलेख युक्तियुक्त समय पर आयुक्त या निर्धारण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खोलेगा और आयुक्त या निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, विलासिता प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रभार के सही सही अभिनिश्चित के प्रयोजन के लिए जो भी आवश्यक हो, ऐसी प्रतियों को ले सकेगा या मंगवा सकेगा या उक्त अभिलेख को निकलवा सकेगा ।

(3) यदि आयुक्त या निर्धारण अधिकारी यह विश्वास करने का कारण है कि स्वत्वधारी अपवंचन या उससे देय कर का संदाय अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है तो उसे जो भी आवश्यक हो, स्वत्वधारी के लेखों, रजिस्टरों या कारणों को लिखित में अभिलेख करने के लिए कर सकेगा और उसके लिए रसीद जारी करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के संबंध में जितने समय तक आवश्यक हो उनको रखेगा :

परंतु अभिग्रहण किए गए लेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों के अभिलेखों को अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखेगा जब तक कि उक्त अवधि से परे उसे रखने के लिए कारणों का लिखित में अभिलेख नहीं कर लिया जाता और आयुक्त का अनुमोदन मामले में प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया जाएगा और ऐसा अनुमोदन किसी भी मामलों में

ऐसे समय में साठ दिन से अधिक नहीं होगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रयाजनों के लिए आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी स्वत्वधारी के कारबाह के किसी होटल या प्रतिभोज कक्ष या किसी स्थान या कोई अन्य स्थान जहां उन्हें यह विश्वास करने का कारण है कि स्वत्वधारी ने अपने कारबाह से संबंधित लेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों के अभिलेखों को तत्समय के लिए रखा हुआ है, प्रवेश और तलाशी कर सकेंगे ।

(5) अन्य व्यक्ति, आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी जो सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो जैसा आयुक्त लिखित में प्राधिकृत कर सके की पूर्व अनुमति के बिना किसी परिसर में प्रवेश और तलाशी नहीं लेगा ।

(6) निर्धारण प्राधिकारी, स्वत्वधारी जिसमें कोई उपनिहित या कोई परिवाहक भी सम्मिलित है के कारबाह के संबंध में किसी व्यक्ति के कथन को अभिलेख करने की शक्ति होगी और ऐसे कथन, कर के स्वत्वधारी के दायित्व को अवधारण करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाए गए प्रभावित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर सकेगा ।

## अध्याय 7

### शास्तियां

रजिस्टर होने में  
असफलता के लिए  
शास्तियां ।

कर संदेय में  
असफल होने के  
लिए शास्तियां ।

विवरणी फाइल में  
असफल होने पर  
शास्ति ।

27. जो कोई धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने में असफल होता है तो देय कर की रकम के अतिरिक्त देय निधारण के रूप में कर की रकम की दुगुनी शास्ति संदेय करने का दायी होगा और रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की तारीख से दायी स्वत्वधारी व्याज संदेय करने का दायी होगा ।

28. यदि कोई स्वत्वधारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर की रकम को संदेय करने में असफल रहता है तो वह दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से भी उस पर शास्ति उसके द्वारा संदेय कर और व्याज के अतिरिक्त संदाय करने का दायी होगी ।

29. यदि कोई स्वत्वधारी, बिना किसी पर्याप्त कारण के निम्नलिखित में असफल रहता है तो,-

(क) विनिर्दिष्ट तारीख द्वारा कोई विवरणी या वार्षिक विवरण देने में ; या

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर की रकम का सबूत विवरणी सहित देने में ; या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कोई त्रुटि या किसी विवरणी या विवरण का लोप के परिशोधन में ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस की अपेक्षाओं के अनुपालन में,

आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी, यथास्थिति इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कर व्याज और शास्ति के अतिरिक्त ऐसे व्यतिक्रम के लिए सौं रूपए प्रतिदिन की राशि की शास्ति जो कि तथापि अधिकतम दस हजार रुपए हो सकेगी उसे संदाय करने का निर्देश कर सकेगा ।

30. जहां कोई स्वत्वधारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कर संगृहित करता है, तो वह कर के संदाय के अतिरिक्त संगृहित किए गए कर का डेढ़ गुणा के

कर के अप्राधिकृत  
संग्रहण के लिए

शास्ति।

कर के अपवंचन के लिए शास्ति।

बराबर शास्ति की राशि संदेय करने का दायी होगा।

31. यदि यथास्थिति, आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि स्वत्वधारी ने कर की रकम के आदेश का निम्नलिखित अपवंचन या परिवर्जन किया है:-

(क) उसके द्वारा कोई विवरणी फाइल से कोई विवरण छिपाया है ; या

(ख) किसी विवरणी में जानबूझकर गलत विवरण दिया है ; या

(ग) उसके लेखाबही से किसी संव्यवहार को छिपाया है ; या

(घ) उवित और सही लेखे का जिसे आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ने उससे देय कर के निर्धारण को निवारित किया हो का रखखाव नहीं किया हो

तो वह स्वत्वधारी को कर के अतिरिक्त शास्ति और कर के रकम के दुगुने के बराबर की राशि उसके द्वारा संदाय व्याज, जो निर्धारित किया जा सके, संदेय करने के लिए निदेश दे सकेगा।

32. (1) कोई स्वत्वधारी, जो धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित किसी संव्यवहार के लिए बिल या कैश मीमो जारी करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे संव्यवहार से संबंधित कर की रकम की दुगुनी शास्ति या पांच हजार रुपए जो भी उच्चतर हो, संदेय करने का दायी होगा।

(2) कोई स्वत्वधारी, मिथ्या बिल या कैश मीमो या प्रयोग किए गए बिल या कैश मीमो जो मिथ्या के नाम से पहचाने जाते हैं को जारी करता है तो वह ऐसे मिथ्या बिल या कैश मीमो में दर्शित रकम पर देय कर की रकम के दुगुने के बराबर शास्ति संदेय करने का दायी होगा।

33. कोई स्वत्वधारी जो यह जानते हुए कोई मिथ्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या कर के संदाय के अपवंचन की दृष्टि के साथ किसी दूसरे स्वत्वधारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त उपर्युक्त कारणों से बचने पर कर की रकम के बराबर शास्ति संदेय करने का दायी होगा।

34. जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर या उद्ग्रहण व्याज या उस पर अधिरोपित शास्ति या उससे कोई अन्य देय रकम मांग नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर संदाय करने में असफल रहता है तो वह अवधि के लिए ऐसी कर की रकम, शास्ति, व्याज या कोई अन्य रकम पर दो प्रतिशत की दर के बराबर शास्ति संदेय करने का दायी होगा, जिसके लिए ऐसी देय रकम संदत्त की गई थी उस तारीख के पश्चात् उसके द्वारा संदाय करने में विलंब किया गया है।

35. (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन के उल्लंघन या असफल होता है यदि ऐसे उल्लंघन या असफल के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य शास्ति प्रदान नहीं की जाएगी तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट तारीख के अंदर दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति संदेय करने का दायी होगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् ऐसे उल्लंघन या असफलता जारी रहती है तो स्वत्वधारी तारीख से एक सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति और संदेय करने का दायी होगा।

36. आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम होगा। यद्यपि, कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक

बिल या कैश मीमो को जारी करने में असफल होने के लिए शास्ति।

रजिस्ट्रीकरण संख्या के दुरुपयोग के लिए शास्ति।

कर की निर्धारित रकम के संदाय के लिए शास्ति।

अन्यत्र कहीं सम्मिलित नहीं मामलों में शास्ति।

शास्ति अधिरोपित करने के लिए

सक्षम प्राधिकारी ।

प्रभावित स्वत्वधारी को नोटिस तारीख के माध्यम द्वारा सुने जाने का अवसर प्रदान न किया हो ।

### अध्याय 8

#### अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, निर्देश और परिशोधन

अपील ।

37. (1) आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई स्वत्वधारी उसके विरुद्ध किए गए आदेश की प्राप्ति की तरीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :

परंतु यह कि अपील प्राधिकारी उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उस अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।

(2) किसी अपील को ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि, कर, शास्ति और व्याज यदि कोई हो की रकम का कुल पच्चीस प्रतिशत से कम का पूर्व संदाय के समाधानप्रद सबूत के साथ संलग्न करता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील को ग्रहण करने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्-

(क) पुष्टि, कम करना, बढ़ाना, वार्षिक या निर्धारण का उपांतरण, व्याज या शास्ति ; या

(ख) निर्धारण, व्याज या शास्ति को अपास्त करना और ऐसी जांच के पश्चात् एक नया आदेश पारित का निर्धारण प्राधिकारी को निर्देश दे सकेगा, जो निर्दिष्ट किया जा सके ; या

(ग) ऐसा आदेश पारित करे जो वह ठीक समझे ।

(4) अपीली प्राधिकारी, किसी अपील को ग्रहण करते समय स्वत्वधारी को मामले के समक्ष नया या अतिरिक्त सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति देगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि स्वत्वधारी निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उसे पर्याप्त कारण के द्वारा प्रस्तुत करनेके लिए निषिद्ध किया गया था और वहां ऐसे साथ्य प्रस्तुत करने के उसके भाग पर जानबूझकर या अयुक्तियुक्त लोप नहीं किया गया था ।

(5) उपधारा (3) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश स्वत्वधारी को और निर्धारण प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी और आयुक्त को भी संसूचित किया जाएगा ।

38. (1) आयुक्त, को आदेश द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निर्धारण प्राधिकारी या कोई अधिकारी द्वारा पारित आदेश के किसी भी समय पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त होगी, जो वह या तो स्वप्रेरणा से या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उसको प्रस्तुत स्वत्वधारी के आवेदन पर करेगा :

परंतु राज्य सरकार साठ दिन के अवसान के पश्चात् किंतु पूर्व अवसान के पश्चात् साठ दिन से परे नहीं प्रस्तुत स्वत्वधारी के आवेदन को ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उस अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था ।

(2) राज्य सरकार, अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश

पुनरीक्षण ।

पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया आदेश, यथास्थिति, स्वत्वधारी और प्राधिकारी या अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण फाइल की गई थी को संसूचित किया जाएगा ।

भूल का परिशोधन ।

39. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल के परिशोधन की दृष्टि से निर्धारण प्राधिकारी, अपीली प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी यथास्थिति किसी भी समय पर किंतु संशोधन या ऐसे आदेश का परिशोधन उसके द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जा सकेगा:

परंतु जहां ऐसे परिशोधन किसी निर्धारण को बढ़ाता है या अन्यथा स्वत्वधारी के दायित्व को बड़ा कर सकेगा, ऐसे आदेश को पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति, निर्धारण प्राधिकारी, अपीली प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी, स्वत्वधारी को ऐसा करने का नोटिस नहीं देगा और उसे सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित कोई आदेश इस अधिनियम के उन उपबंधों के अधीन पारित आदेश समझा जाएगा जो कि मूल आदेश के अधीन जारी किया गया था ।

(3) जहां ऐसे परिशोधन निर्धारण या शास्ति को कम कर सके, निर्धारण प्राधिकारी, प्रतिदाय करेगा, जो स्वत्वधारी को देय किया जा सके ।

(4) जहां ऐसे परिशोधन कर या शास्ति या ब्याज या प्रतिदाय की रकम को कम करने की रकम को बड़ा सकेगा, यथास्थिति आयुक्त, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय रकम की वसूली के लिए आदेश पारित करेगा ।

40. (1) कोई अधिकारी, जो कि उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो ऐसी रीति में और ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जा सके, या तो स्वप्रेरणा से या लिखित में आदेश द्वारा इस निमित्त उसके आदेदन पर कोई मामला या कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग को अपने से उसके अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य अधिकारी को अंतरण कर सकेगा और इसी तरह से किसी अधिकारी से अन्य अधिकारी या स्वर्य से इस धारा के अधीन पहले से ही अंतरित किए गए जो मामलों को अंतरण कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अंतरित कोई कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग या मामले, किए गए हैं तो अधिकारी ऐसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग या अंतरित मामले को वह निपटान करने की कार्यवाही करेगा, यदि उसकी अधिकारिता की स्थानीय परिसीमा को विचार में लाए बिना उसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा और ऐसे अंतरण, ऐसे अंतरण से पहले से ही जारी किसी नोटिस के पुनः जारी करने को आवश्यक नहीं बनाया जाएगा और अधिकारी जो कार्यवाही या अंतरित मामलों को अपने विवेकाधिकार से किसी भी स्तर से चालू कर सकेगा जिस प्राधिकारी द्वारा उसे इसे अंतरित किया है और छोड़ दिया है ।

41. (1) कोई स्वत्वधारी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में प्राधिकारी के पास उपस्थित होने का हकदार या अपेक्षित है इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा । स्वत्वधारी के संबंधी या पूर्णकालिक कर्मचारी या कोई अधिवक्ता या कर परामर्शदाता को उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निरर्हित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'कर परामर्शदाता' से अभिप्रेत है:-

प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से स्वत्वधारी को उपस्थित होने की अनुज्ञा ।

(क) पंजाब उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग का सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए या तो कर प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या दोनों के रूप में कार्य किया है ; या

(ख) कोई व्यक्ति, जिसने विधि द्वारा निगमित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वाणिज्य, विधि, आर्थिकी, बैंकिंग, लेखा परीक्षा में डिग्री रखता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवा से बर्खास्त हुआ है उपधारा (1) के अधीन किसी स्वत्वधारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होगा ।

(3) यदि कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति, जो स्वत्वधारी का प्रतिनिधित्व करता है आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में अवचार का दोषी पाया जाता है तो आयुक्त यह निर्देश कर सकेगा कि वह उपधारा (1) के अधीन स्वत्वधारी के प्रतिनिधित्व से निरहित किया जाएगा:

परंतु ऐसा निर्देश किसी व्यक्ति के संबंध में जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता ।

(4) किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई निर्देश उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए हैं तो वह उसे संसूचित करने के साठ दिनों की अवधि के भीतर ऐसे निर्देश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

42. ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन जो विहित किए जा सकें, आयुक्त लिखित में आदेश द्वारा उसकी सहायता करने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

43. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रस्तुत कोई विवरणी या लेखों या दस्तावेजों में अंतर्विष्ट या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में दिए गए किसी साक्ष्य में विधि के न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को छोड़कर सभी विशिष्टियां गोपनीयता के रूप में मानी जाएंगी ।

(2) इस धारा की कोई बात ऐसी विवरणी, लेखों, दस्तावेजों या साक्ष्यों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अधीन किसी जांच या अभियोजन के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों या भारत सरकार के विभाग के शासकीय प्रयोग के प्रयोजन के लिए या किसी व्यक्ति द्वारा कारबाह के संव्यवहार के संबंध में किसी जांच के प्रयोजन के लिए जो ऐसे संव्यवहार में एक पक्ष है, के स्पष्टीकरण को लागू नहीं होगी ।

44. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई अधिकारी, जब कभी अपेक्षित हो, राज्य सरकार के किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी से सहायता ले सकेगा और पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी ऐसे अनुरोध पर यथास्थिति, विधि के अनुसरण में आवश्यक सहायता करेगा ।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन या उसको प्रदत्त कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त या अधिकारी निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबंधों के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों को रखेगा, अर्थात्:-

(क) समन कराना और किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

विवरणियों आदि की गोपनीयता रखना ।

पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी से सहायता मांगने की शक्ति ।

साक्षी को समन और अभिलेखों को प्रस्तुत करने की शक्ति ।

उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों को पूर्ण प्रस्तुत करना और उसको परिवद्ध करना ;

(ग) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत ; और

(घ) साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी करना ।

(2) किसी शपथ पत्र की दशा में धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के समक्ष या धारा 3 के अधीन आयुक्त की सहायता करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और 228 और इस संहिता की धारा 199 के प्रयोजन के लिए किसी कार्यवाही के अर्थ के अंतर्गत 'न्यायिक कार्यवाही' समझी जाएगी ।

कार्यवाही का  
वर्जन ।

46. (1) इस अधिनियम के अधीन निर्धारण किए जाने या पारित आदेश को अपास्त या उपांतरण कोई वाद करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योगी के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो ।

नियम बनाने की  
शक्ति ।

47. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के ग्राहोजन को क्रियान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों को ढाना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित किसी मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 4 की उपधारा (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा कर को संदर्भ करने की रीति ;

(ख) धारा 7 के अधीन घोषित की गई विलासिता के लिए साधारण दर की रीति और अवधि ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति और उसके लिए फीस विहित करना ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन स्वत्वधारी का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रलूप विहित करने की रीति ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (3) के दूसरे पंस्तुक के अधीन स्वत्वधारी द्वारा विवरणी करने फाइल करने और देख रकम का संदाय करने की रीति ;

(च) धारा 9 के अधीन आयुक्त को सूचित करनेकी रीति ;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (6) के अधीन क्रमशः प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति और रकम के लिए और प्रतिभूति देने के लिए रीति ;

(ज) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन स्वयं निर्धारण फाइल करने के लिए विहित प्रलूप ;

(ज्ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा कर के संदाय का संतोषप्रद सबूत देने के लिए रीति ;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विवरणी के सत्यापन के लिए रीति ;

(ट) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा विलंब अवधि के लिए अतिरिक्त कर की रकम का संदाय करने के लिए विहित रीति ;

(ठ) धारा 14 की उपधारा (11) के अधीन मांग नोटिस का विहित प्रस्तुप जिसमें संदेय राशि विनिर्दिष्ट करना ;

(ड) धारा 22 के अधीन कर, शास्ति या ब्याज की रकम स्वत्वधारी को प्रतिदाय करने के लिए विहित रीति और अवधि ;

(ढ) धारा 25 के अधीन विहित अन्य रजिस्टर या अभिलेख ;

(ण) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन स्वत्वधारी से लेखा अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या निर्धारण प्राधिकारी से उसके कारबाहर से संबंधित कोई जानकारी देने की अपेक्षा करने की शर्त विहित करना ;

(त) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन स्वत्वधारी द्वारा की जाने वाली अपील के लिए प्राधिकारी विहित करना ;

(थ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन जिसमें वह रीति और शर्तों जिसके अध्यधीन रहते हुए निर्धारण प्राधिकारी, किसी मामले या कार्यवाही या कार्यवाही के किसी वर्ग को अंतरित कर सकेगा ; और

(द) वे शर्त विहित करना जिनके अधीन रहते हुए आयुक्त धारा 42 के अधीन किसी अधिकारी को अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा ; और

(ध) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाने जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त सत्र के अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की या लोप किए जाने की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

48. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और  
व्यावृति ।

49. (1) पंजाब विलासिता पर कर अध्यादेश, 2008 (2008 का पंजाब अध्यादेश सं.  
4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उक्त अध्यादेश के अधीन  
की गई कोई वात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई  
समझी जाएगी।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2011

**G.S.R. 600(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Tax on Luxuries Act, 2009 (Punjab Act No. 4 of 2009), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:—

### MODIFICATIONS

1. Throughout the Act, for the words “State Government”, wherever they occur, the word “Administrator”, shall be substituted.
2. In section 1, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—  
“1(A) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.”
3. In section 2, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—  
“(a) “Administrator” means the Administrator of the Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution;  
(aa) “assessing authority” means an officer appointed as such by the Administrator by notification in the Official Gazette to make an assessment under this Act;”
4. In section 3, in sub-section (2), for the words “State of Punjab”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted.
5. In section 18, the words “enacted by the Punjab State Legislature” shall be omitted.
6. In section 41, in sub-section (1), in the explanation in clause (a), for the word “Punjab” the word “Chandigarh”, shall be substituted.
7. In section 47, in sub-section (3),—  
(a) for the words “House of the State Legislature”, the words “each House of Parliament”

(b) for the words, “ten days”, the words “thirty days”, shall be substituted.

8. In section 48, in sub-section (2), for the words “House of the State Legislature”, the words “each House of Parliament” shall be substituted.

9. Section 49 shall be omitted.

[F. No. U-11020/3/2010-UTL]

M. GOPAL REDDY, Jt. Secy.

### ANNEXURE

#### THE PUNJAB TAX ON LUXURIES ACT, 2009 (PUNJAB ACT NO. 4 OF 2009)

1	(1) This Act may be called the Punjab Tax on Luxuries Act, 2009.	Short title and commencement
	(2) It shall come into force at once.	

#### CHAPTER-I PRELIMINARY

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- definitions

- (a) “assessing authority” means an officer, appointed as such, by the State Government by notification in the Official Gazette to make an assessment under this Act;
- (b) “banquet hall” means any premises, garden or farm house, marriage palace or any part thereof, where accommodation or space is let out for a monetary consideration for marriages, receptions, conventions, banquets, kitty-parties, meetings or exhibitions for sale of goods or for arranging functions or events whether on regular or periodical or occasional basis;
- (c) “charges for luxury provided in a banquet hall” includes an amount received by way of donation or charity or by whatever name called for luxury provided in a banquet hall;
- (d) “Commissioner” means an officer, appointed as the Excise and Taxation Commissioner by the State Government under sub-section (1) of section 3;

- (e) “concessional rate” means a rate, lower than the normal rate, fixed for a luxury by the proprietor ;
- (f) “hotel” means any premises including lawn, lodging house, club, if any, or a holiday resort, let out whether on regular or periodical or occasional basis for a monetary consideration ;
- (g) “luxury” means the services, rendered for the purpose of enjoyment, comfort or pleasure ;
- (h) “luxury provided in a banquet hall” means the luxury, provided by way of accommodation or space in a banquet hall on payment of a sum, not less than five thousand rupees per occasion or such other sum, as may be specified by the State Government by notification, which shall include the charges for air cooling, air conditioning, chairs, tables, linen, utensils and vessels, shamiana, tent, pavilion, electricity, water, fuel, interior or exterior decoration, music orchestra, live telecast or other such like amenities whether such charges are received collectively or separately, but excluding the charges for food and drinks ;

*Explanation.*—While calculating the sum of five thousand rupees or any other specified sum, the charges for providing the aforesaid amenities, shall be taken into account collectively, even if charges for any of the amenities are received separately by the proprietor or by any other person on his behalf ;

- (i) “luxury provided in a hotel” means a luxury, provided by way of accommodation for lodging in a hotel on payment of a sum, not less than two hundred rupees per day or such other sum, as may be specified by the State Government by notification, which shall include the charges for air-conditioning, telephone, fax, internet, television, radio music, health club, beauty parlour, swimming pool, conference hall or other such like amenities whether such charges are received collectively or separately, but excluding the charges for food and drinks ;

*Explanation.*—While calculating the sum of two hundred rupees or any other specified sum, the charges for providing the aforesaid amenities, shall be taken into account collectively, even if charges for any of the amenities are received separately by the proprietor or by any other person on his behalf ;

- (j) "normal rate" means the rate, charged from any user after giving the discounts as per ordinary practice in a hotel or banquet hall, but excluding the cash discount, if any ;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (l) "proprietor" means any person, who is an owner or a contractor or a lessee, managing a hotel or a banquet hall, as the case may be, in any capacity, and includes the person, who for the time being, is managing the affairs of such hotel or banquet hall ;
- (m) "section" means a section of this Act ;
- (n) "State Government" means the Government of the State of Punjab in the Department of Excise and Taxation ;
- (o) "tax" means the luxury tax, levied and collected under this Act ; and
- (p) "year" means the financial year.

3. (1) For carrying out the purposes of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint an officer, to be the Commissioner and such other officers to assist him, as it may deem appropriate. Commissioner and other officers.

(2) The commissioner shall have jurisdiction over whole of the State of Punjab and shall have all the powers and perform all the duties, conferred or imposed upon him by or under this Act. All other officers, appointed under sub-section (1), shall exercise such powers, as may be conferred upon them by the State Government.

(3) Every Officer, appointed under sub-section (1), to assist the Commissioner, shall exercise his powers, subject to the general superintendence and control of the Commissioner.

## CHAPTER – II

### LEVY OF TAX ON LUXURY PROVIDED IN HOTELS AND BANQUET HALLS

4. (1) Every proprietor shall be liable to pay tax under this Act, on the amount received by him for luxury, provided in a hotel on daily basis, at such rate, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette, but such tax shall not exceed fifteen per cent of the total received amount. Levy of tax on hotels.

(2) In case, an amount is received by a proprietor for luxury, provided in a hotel, other than on daily basis, the tax liability shall be determined by taking into consideration, the daily average charges of the amount so received :

Provided that the tax shall be levied only if, the charges for luxuries are more than two hundred rupees per day or such other sum, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette.

(3) The tax levied under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall be paid by the proprietor in such manner, as may be prescribed.

Levy of tax on  
banquet halls.

5. (1) Every proprietor shall be liable to pay tax under this Act on the amount received by him for luxury, provided in a banquet hall, at such rate, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette, but such tax shall not exceed fifteen per cent of the total received amount :

Provided that the tax shall be levied only, if the charges for luxuries are more than five thousand rupees per day or such other sum, as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette.

(2) The tax levied under sub-section (1), shall be paid by the proprietor in such manner, as may be prescribed.

Method of  
calculation  
of tax.

6. (1) Where the charges for luxury, provided in a hotel or a banquet hall, as the case may be, are inclusive of the charges for food and drink, the assessing authority may, after giving the proprietor an opportunity of being heard, segregate the charges separately i.e. charges for luxury and charges for food and drink.

(2) Where any service charges, other than the charges for luxury, provided in a hotel or a banquet hall, as the case may be, are collected and appropriated either wholly or partly by the proprietor, and are not paid to the staff, such charges shall be deemed to be the part of the charges for luxury.

(3) Where luxury in a hotel or banquet hall, as the case may be, is provided to any person free of cost or at a concessional rate, the tax shall be levied at the normal rate for such luxury.

(4) Where luxury was to be provided in a hotel at a normal rate to certain specified number of persons, but actually the same was availed of by more than the specified persons, then the tax shall also be levied on the extra persons at the same rate.

7. Every proprietor liable to pay tax, shall declare the normal rates for luxuries, provided by him in such manner and within such period, as may be prescribed. Declaration of charges.

### CHAPTER – III

#### REGISTRATION

8. (1) No proprietor, who is liable to pay tax under this Act, shall provide luxury in a hotel or banquet hall, unless he is registered under this Act. Registration.

(2) Every proprietor, required to be registered under sub-section (1), shall make an application for registration to the Commissioner, within a period of thirty days from the date, when such proprietor becomes liable to pay tax under this Act alongwith such fee and in such manner, as may be prescribed.

(3) If the Commissioner is satisfied that the application made under sub-section (2), is in order, he shall, in accordance with such manner, as may be prescribed, register the proprietor and grant him a registration certificate in such form, as may be prescribed :

Provided that if the Commissioner is satisfied that the particulars, contained in the application, are not correct or are incomplete or that any evidence or information, required for registering the proprietor, is not furnished, he may, after making an inquiry and giving the proprietor an opportunity of being heard, reject the application for reasons, to be recorded in writing. However, after furnishing the required information or correcting the application, as desired by the Commissioner, the proprietor may submit a fresh application for registration in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder :

Provided further that during the pendency of an application for registration, the proprietor shall file return and pay the due amount of tax in such manner, as may be prescribed.

Information to be furnished regarding change of business.

9. If any proprietor,—

- (a) sells or otherwise disposes of his business or any place of business ; or
- (b) discontinues or transfers his business or changes his place of business or opens a new place of business ; or
- (c) changes the name, constitution or nature of his business ; or
- (d) appoints an agent,

he shall inform the Commissioner in this regard in such manner, as may be prescribed. In case of death of a proprietor, his legal representative shall inform the Commissioner in such manner, as may be prescribed :

Provided that if a proprietor or his legal representative, as the case may be, fails to inform the Commissioner in respect of the changes, then, notwithstanding any such change, the tax due from such proprietor, shall be recovered as if no change has taken place :

Provided further that in the case of transfer of business, the transferee or his successor, as the case may be, shall also be liable to pay the tax, due under this Act.

Changes in registration.

10. Consequent upon the receipt of information under section 9, the Commissioner shall, by an order in writing, make necessary changes in the relevant record.

Cancellation of registration.

11. (1) The Commissioner may, on an application, made to him by the proprietor for cancellation or otherwise on information that the proprietor has,—

- (a) discontinued his business ; or
- (b) violated any of the provisions of this Act or the rules made thereunder ; or
- (c) not made the payment of the tax, due under this Act ; or
- (d) not filed the return, as required under this Act ; or
- (e) misused his registration,

cancel the registration.

(2) No registration, otherwise than on an application of the proprietor, shall be cancelled without giving him an opportunity of being heard.

12. (1) Every proprietor applying for registration under this Act, shall furnish a security of rupees fifty thousand in such manner, as may be prescribed, for securing proper and timely payment of tax or any other sum, payable by him under this Act. Security from proprietors.

(2) The Commissioner may, on an application, made to him by the proprietor for release, discharge or refund of security, furnished by him under sub-section (1), order the release, discharge or refund of the whole or any part thereof, if the same is not required.

(3) Where it appears expedient to the Commissioner so to do, for proper realisation of tax, payable under this Act, he may, at any time while such registration is in force, by an order in writing and for the reasons, to be recorded therein, require the proprietor to furnish within such time, as may be specified in the order and in the prescribed manner, such additional security, not exceeding rupees two lac in addition to the security, already furnished under sub-section (1), as may be specified in the order for the aforesaid purpose :

Provided that no proprietor shall be required to furnish any additional security under this sub-section, unless he has been given an opportunity of being heard.

(4) The Commissioner shall not retain the security, furnished by a proprietor, if the registration of such proprietor has been cancelled and nothing remains due against him.

(5) The Commissioner may, by an order in writing, for good and sufficient cause, forfeit the whole or any part of the security or additional security, furnished by a proprietor for recovery of any amount of tax or penalty, due or payable by him under this Act :

Provided that no order shall be made under this sub-section without giving the proprietor an opportunity of being heard.

(6) In case, the security is rendered insufficient because of the order made under sub-section (5), the proprietor shall furnish further security to make up for the amount, which has fallen short in such manner, as may be prescribed and within such time, as may be specified.

## CHAPTER – IV

RETURNS, ASSESSMENT, PAYMENT, RECOVERY AND  
COLLECTION OF TAX

Self assessment,  
returns and  
payment of tax.

13. (1) Every proprietor shall make self assessment of the tax, payable by him under this Act, and shall file a return in such form, as may be prescribed, in this regard to the Commissioner or to any other officer, authorised by him within a period of sixty days from the date of expiry of the year.

(2) Every proprietor shall pay the full amount of tax, payable by him before filing the return, and shall furnish alongwith the return, a satisfactory proof of the payment of such tax in such manner, as may be prescribed. Any return without such proof, shall not be entertained.

(3) Every return shall be verified in such manner, as may be prescribed.

(4) Every proprietor shall make monthly payment of tax within a period of fifteen days from the date of expiry of the month, and shall furnish to the Commissioner or any other officer, authorised by him, a statement in this regard in the prescribed form. Such statement shall be accompanied by a satisfactory proof of payment of the full amount of due tax. A statement without such proof of payment, shall not be entertained.

(5) If there is a default in the payment of due tax for any month, beyond a period of ten days, whether a statement, as required under sub-section (4), is furnished or not, the defaulting proprietor shall, in addition to making payment of due tax, pay interest also at the rate of two per cent per month or part thereof, from the date of such default.

(6) If a proprietor discovers any *bona-fide* error or omission in any return, furnished by him, he may rectify such error or omission by filing a revised return immediately after the detection of such error or omission. If such rectification results in a higher amount of tax, to be due than the one, shown in the original return, the same shall be accompanied by the receipt of payment of the higher or the additional amount of tax payable, alongwith the interest at the rate of two per cent per month for the period of delay in such manner, as may be prescribed. No such rectification shall, however, be allowed after the end of the year immediately following the year to which the rectification relates or after the issuance of a notice for assessment, whichever is earlier. Where such rectification results in excess amount of tax having been paid than the due tax, such excess amount shall be refunded on application made by the proprietor in such manner, as may be prescribed.

**14. (1)** Where on scrutiny of a return filed either under sub-section (1) or sub-section (6) of section 13, any tax or interest is found to be due after adjustment of any tax or interest paid on self-assessment or otherwise, then, without prejudice to the provisions of sub-section (2), an intimation sent to the proprietor in this regard by the assessing authority, shall be deemed to be a notice of demand, served under sub-section (1), and all the provisions of this Act shall apply accordingly :

Assessment of tax.

Provided that the acknowledgement of return shall be deemed to be an intimation, in case, no sum is payable by the proprietor or no refund is due to him :

Provided further that no intimation under this sub-section, shall be sent after the expiry of a period of two years from the date of expiry of the year in which the return is filed.

**(2)** Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Commissioner may, on his own motion or on the basis of the information received by him, make an assessment of the tax, payable by a proprietor to the best of his judgement and determine the tax payable by him, where,—

- (a) the proprietor has not filed the return under section 13 ; or
- (b) there are definite reasons to believe that the return filed by a proprietor, is not correct and complete ; or
- (c) there are reasonable grounds to believe that the proprietor has not paid the due amount of tax ; or
- (d) provisional assessment has been made.

**(3)** The Commissioner on his own motion or on the basis of the information received by him, may, by an order in writing, direct the assessing authority to make an assessment of the amount of tax, payable by any proprietor for such period, as he may specify.

**(4)** An assessment under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, may be made within a period of three years from the date, when the return was filed or due to be filed, whichever is later :

Provided that where circumstances so warrant, the Commissioner may, by an order in writing, allow assessment of a proprietor after three years, but not later than six years from the date, when return was filed or due to be filed, whichever is later.

(5) Where an assessment is to be made under this section, the assessing authority shall serve a notice to the concerned proprietor and such notice shall state—

- (a) the grounds for the proposed assessment ; and
- (b) the time, place and manner for filing objections, if any.

(6) The assessing authority after taking into account all the relevant material, available with it, shall, on the date, specified in the notice, served under sub-section (5) or soon thereafter, as the case may be, and after taking into consideration such evidence, as may be produced by the proprietor, by an order in writing, make an assessment, determining the sum, payable by or refundable to the proprietor on the basis of such assessment.

(7) The assessing authority may, with the prior permission of the Commissioner, amend an assessment, made under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, within a period of three years from the date of the order of assessment, if it discovers under-assessment of tax, payable by a proprietor for the reason that—

- (a) such a proprietor has committed fraud or wilful neglect ; or
- (b) such a proprietor has misrepresented ; or
- (c) a part of the amount, received on account of luxury provided in a hotel or a banquet hall, has escaped assessment.

(8) The assessing authority may, within a period of one year from the date of assessment order, rectify an assessment, made under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, if it discovers that there is a mistake apparent on the face of the record.

(9) An assessment, referred to in sub-section (7) or sub-section (8), shall be an assessment, made under this Act for all intents and purposes.

(10) No assessment or other proceeding purported to be made or taken under this Act or the rules made thereunder, shall be—

(a) quashed or deemed to be void for the reason that the same was not in the prescribed form ; or

(b) affected by reason of a mistake, defect or omission therein :

Provided that such an assessment is substantially in conformity with the provisions of this Act and the rules framed thereunder.

(11) When any tax, interest, penalty or any other sum is payable in consequence of any order made under this Act, the assessing authority shall serve upon the proprietor, a notice of demand in the prescribed form specifying therein the sum, so payable.

(12) No order under this section shall be made without affording an opportunity of being heard to the proprietor concerned.

15. (1) Notwithstanding anything contained in section 14, where a <sup>Provisional assessment.</sup> fraud or wilful neglect has been committed with a view to evade or avoid the payment of tax or due tax has not been paid or a return has not been filed by or on behalf of a proprietor, the assessing authority may, for the reasons, to be recorded in writing, make provisional assessment for any period to determine the tax liability so evaded, avoided or the tax so unpaid :

Provided that the tax liability of such a proprietor shall be assessed finally after he files his return in the prescribed manner :

Provided further that in addition to the tax so assessed in such provisional assessment, the proprietor shall be liable to pay a penalty of double the amount of tax so assessed.

(2) The provisional assessment under sub-section (1), shall be made within a period of six months from the date of detection of fraud or wilful neglect. The Commissioner may, however, for the reasons, to be recorded in writing, on a reference made by the assessing authority, extend the said period by another six months.

16. (1) If a proprietor, fails to pay the amount of tax due from him under this Act, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay interest on the said amount of tax at the rate of two per cent per month from the due date of payment till the date, he actually pays such tax alongwith the interest.

<sup>Interest on non-payment or delayed payment of tax.</sup>

(2) When a revised return filed under sub-section (6) of section 13, shows higher amount of tax due, the proprietor shall be liable to pay interest at the rate of two per cent per month on such higher amount of tax from the due date till the date, he actually pays the due amount of tax alongwith the interest.

(3) If a proprietor fails to declare the amount of tax in the return, which should otherwise have been declared, such proprietor shall be liable to pay interest at the rate of two per cent on such amount of tax from the due date till the date, he actually pays such amount of tax.

(4) If the amount of tax or penalty due from a person, is not paid by him within the period, specified in the notice of demand or if no such period is specified, within a period of thirty days from the date of service of such notice, the proprietor shall, in addition to the payment of amount of tax or penalty, be liable to pay interest on such amount at the rate of two per cent per month from the date, the tax is due till the date, he actually pays the due amount of tax or penalty, as the case may be, alongwith the interest :

Provided that where the recovery of tax or penalty, as the case may be, is stayed by an order of the competent authority, the amount of tax or penalty shall, after the order of stay is vacated, be recoverable alongwith the interest at the aforesaid rate on the amount, ultimately found to be due and such interest shall be payable from the date, the tax or penalty had first become due.

(5) The amount of interest payable under this section shall,—

- (a) be calculated by considering part of a month as a full month;
- (b) for the purposes of collection and recovery, be deemed to be tax under this Act; and
- (c) be in addition to the penalty, if any, imposed under this Act.

*Explanation.*—For the purpose of this section, if payment of tax is made by the proprietor through cheque, and the cheque is dishonoured by the bank, then it will amount to failure on the part of the proprietor to pay tax.

Tax as a debt due  
to the State  
Government.

17. The tax or any other amount due or payable by a proprietor under this Act, shall be a debt due to the State Government, and shall be paid or recovered as per the provisions of this Act and the rules made thereunder.

18. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, enacted by the Punjab State Legislature, for the time being in force, the amount of tax, penalty, interest or any other sum, payable by a proprietor or any other person under this Act, shall be the first charge on the property of such proprietor or person from the date, on which the amount becomes due and payable.

Liability under this Act to be the first charge

19. Any amount of tax, penalty, interest or any other such sum due and payable under this Act, which remains unpaid after the due date, shall be recoverable as arrears of land revenue.

Unpaid amount recoverable as arrears of land revenue

20. Any payment made by a proprietor towards the amount, due as a result of any order passed under this Act, shall first be adjusted, except in so far as the recovery of such amount or part thereof, is stayed under the provisions of this Act, against the interest payable by him on the date of payment and thereafter, against the amount due as a penalty. Any amount remaining unadjusted thereafter, shall be adjusted against the tax payable.

Adjustment of any payment

21. (1) No proprietor against whom any recovery proceedings under this Act are pending shall create a charge on or part with the possession by way of sale, mortgage, gift, exchange or any other mode of transfer whatsoever of any of his assets with the intention to avoid or evade payment of tax, penalty, interest or any other sum due or likely to become due against him.

Restrictions on transfer of property

(2) Any charge or transfer made in violation of the provisions of sub-section (1), shall be void as against any claim in respect of tax or any other sum, payable by the proprietor till the completion of such proceedings :

Provided that such charge or transfer shall not be void, if it is made with the previous permission of the Commissioner or the payment of tax or any other amount due from such proprietor, has been fully secured by furnishing a bank guarantee. In the case of outstanding arrears, the Commissioner shall take into account any other liability under this Act.

*Explanation.*—For the purpose of this section, 'assets' means land, building, machinery, plant, shares, securities and fixed deposits in the banks to the extent, to which any of the aforesaid assets, do not form part of the stock in trade of the business of the proprietor.

## CHAPTER V

## REFUND

## Refund of tax.

22. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Commissioner shall, in such manner and within such period, as may be prescribed, refund to the proprietor the amount of tax, penalty or interest, if any, paid by such proprietor in excess of the amount due from him. The refund may either be made by refund voucher or at the option of the proprietor, by refund adjustment order :

Provided that the Commissioner shall first apply such excess amount towards the recovery of any amount due, in respect of which, a notice of demand under sub-section (11) of section 14 has been served or towards any other amount, which is due, but not paid, and shall refund the balance amount, if any.

## Interest on delayed refund.

23. (1) Where an amount, required to be refunded under section 22 by the Commissioner to a proprietor, is not so refunded to him within a period of sixty days from the date of application, a simple interest at the rate of half per cent per month on the said amount shall be paid to such proprietor from the date, immediately following the expiry of the said period of sixty days to the date of making refund.

*Explanation.*—If delay in making refund within the aforesaid period of sixty days, is attributable to the proprietor whether wholly or in part, then such period of delay shall be excluded from the period, for which interest is payable.

(2) Where any question arises as to be period, to be excluded in terms of the Explanation to sub-section (1), then such a question shall be determined by the Commissioner, whose decision shall be final.

(3) Interest under this section, shall be calculated by considering part of a month as full one month.

## Power to withhold refund in certain cases.

24. (1) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceeding or where any other proceeding under this Act is pending, and the officer competent to make such refund is of the opinion that making of refund is likely to affect the revenue adversely, such officer may, with the prior approval of the Commissioner, withhold the refund till such time, as may be determined by such officer.

(2) Where a refund is withheld under the sub-section (1), the Commissioner shall pay interest in accordance with the provisions of section 21, on the amount of refund ultimately determined to be due to the proprietor as a result of such appeal or further proceeding or any other proceeding for the period, starting from the date, immediately following the expiry of the period of sixty days from the date of order, referred to in sub-section (1), to the date of making refund.

## CHAPTER-VI

### MAINTENANCE OF ACCOUNTS AND INSPECTION

25. (1) Every proprietor, shall maintain and keep true and complete accounts relating to his business and shall also maintain such other registers or records as may be prescribed. All such accounts, registers or records shall be kept by the proprietor in safe custody till his assessment for the relevant year is completed or in case where an appeal, revision or any other proceeding in respect of such year has been filed or instituted and is pending, the same is disposed of.

Maintenance of accounts and registers etc.

(2) Every proprietor liable to pay tax, shall issue a bill or cash memo in respect of the charges, received for providing accommodation in a hotel or charges, received for providing banquet hall, and shall mention therein, the true amount of such charges, the name and address of the person from whom the same are received. Where such charges are received in any foreign currency, the name of such currency shall be mentioned clearly in such bill or cash memo. The cash memo to be issued by such proprietor, shall bear the full name, address and registration number of the hotel or banquet hall, as the case may be.

26. (1) The Commissioner or the assessing authority, may, subject to such conditions, as may be prescribed, require any proprietor to produce before it, the records of accounts, registers or other documents or to furnish any other information relating to his business, as may be necessary for the purpose of this Act.

Power of inspection and search

(2) All records of accounts, registers or other documents relating to the business of any hotel or banquet hall, shall at all reasonable times, be open for inspection by the Commissioner or the assessing authority, and the Commissioner or the assessing authority, as the case may be, may take or cause to be taken such copies or extract of the said records, as may be necessary for the purpose of ascertaining the accuracy of the charges, received for providing luxury.

(3) If the Commissioner or the assessing authority has reason to believe that a proprietor has evaded or is trying to evade the payment of tax due from him, it may, for the reasons to be recorded in writing, seize such records of accounts, registers or other documents of the proprietor, as may be necessary and shall issue a receipt for the same, and shall retain them so long as may be necessary in connection with any proceedings under this Act :

Provided that the records of accounts, registers or other documents so seized, shall not be retained for a period, exceeding one hundred eighty day from the date of seizure, unless reasons for retaining the same beyond the said period, are recorded in writing and the approval of the Commissioner is obtained in case, the seizure is made by the assessing authority, and such approval in any case, shall not be for more than sixty days at a time.

(4) For the purposes of this Act, the Commissioner or the assessing authority, may enter and search any hotel or banquet hall or any place of business of the proprietor or any other place where they have reason to believe that the proprietor keeps, or is for the time being keeping any records of accounts, registers or other documents relating to his business.

(5) No other person shall enter and search any premises, without the prior permission of the Commissioner or of such other officer, not below the rank of the Assistant Excise and Taxation Commissioner, as the Commissioner may authorize in writing.

(6) The assessing authority shall have the power to record the statement of any person connected with the business of the proprietor including a bailee or a transporter, and such statement may, after giving the affected person a reasonable opportunity of being heard, be used for the purpose of determining the liability of the proprietor to tax.

## CHAPTER-VII

### PENALTIES

**Penalty for failure to register.**

27. Whoever fails to make an application for registration as required under sub-section (2) of section 8, shall be liable to pay penalty of double the amount of tax, as assessed to be due, in addition to the amount of tax, due and the interest payable from the date, the proprietor becomes liable for registration till the application for registration is made.

**Penalty for failure to pay tax.**

28. If a proprietor, fails to pay the amount of tax in accordance with the provisions of this Act, he shall be liable to pay in addition to the tax and the interest payable by him, a penalty thereon also at the rate of two per cent per month.

## 29. If a proprietor without any sufficient cause fails to,—

Penalty for failure  
to file return.

- (a) furnished any return or annual statement by the specified date ; or
- (b) furnish alongwith the return, the proof of payment of tax in accordance with the provisions of this Act ; or
- (c) rectify any error or omission in any return or statement in accordance with the provisions of this Act ; or
- (d) comply with the requirements of any notice, issued under this Act,

the Commissioner or the assessing authority, as the case may be, may, direct him to pay in addition to the tax, interest and penalty under any of the provisions of this Act, a further penalty of a sum of rupees one hundred per day for such default, subject, however, to the maximum sum of ten thousand rupees.

## 30. Where a proprietor collects tax in contravention of the provisions of this Act, he shall, in addition to the payment of tax, be liable to pay a penalty of a sum, equal to one-and-a-half times of the tax, so collected.

Penalty for  
un-authorised  
collection of tax.

## 31. If the Commissioner or the assessing authority, as the case may be, is satisfied that a proprietor, in order to evade or avoid payment of tax, has,—

Penalty for  
evasion of tax.

- (a) concealed any particulars from any return, filed by him ; or
- (b) deliberately furnished incorrect particulars in any return ; or
- (c) concealed any transaction from his account books ; or
- (d) not maintained proper and clear accounts, which prevents the Commissioner or the assessing authority to assess the tax due from him,

he shall direct the proprietor to pay a penalty, in addition to the tax and interest payable by him of a sum, equal to double the amount of the tax, as may be unassessed.

Penalty for failure to issue a bill or cash memo.

32. (1) A proprietor, who fails to issue a bill or cash memo for any transaction as required under sub-section (2) of section 25, shall be liable to pay a penalty of double the amount of tax relating to such transaction or rupees five thousand, whichever is higher.

(2) A proprietor, who issues a false bill or cash memo or uses a bill or cash memo knowing it to be false, shall be liable to pay a penalty, equal to double the amount of tax due on the amount, shown in such false bill or cash memo.

Penalty for misuse of registration number.

33. A proprietor, who knowingly uses a false registration certificate or uses registration certificate of another proprietor with a view to evade payment of tax, shall be liable to pay in addition to the due tax, a penalty equal to the amount of tax, evaded on account of the aforesaid reasons.

Penalty for Non-payment of assessed amount of tax.

34. Where a person fails to make payment of the tax assessed or interest levied or penalty imposed upon him or any other amount due from him under this Act, within a period of thirty days from the date of service of the notice of demand, he shall be liable to pay a penalty equal to two per cent per month on such amount of tax, penalty, interest or any other amount due, in addition to the tax assessed or interest or any other amount due, for the period for which, payment has been delayed by him after the date on which, such amount was due to be paid.

Penalty in cases not covered elsewhere.

35. (1) Whoever, contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, shall, if no other penalty is provided under this Act for such contravention or failure, be liable to pay penalty, not exceeding ten thousand rupees, within the date, specified in this regard by the competent authority.

(2) Where such contravention or failure continues even after the date, as specified under sub-section (1), the proprietor shall be liable to pay a further penalty of rupees one hundred per day from that date.

Authority competent to impose penalty.

36. The Commissioner or the assessing authority, as the case may be, shall be competent to impose penalty under this Act. However, no penalty shall be imposed, unless the affected proprietor is afforded an opportunity of being heard by way of serving a notice.

## CHAPTER-VIII

APPEAL, REVISION, REVIEW, REFERENCE AND  
RECTIFICATION

37. (1) Any proprietor aggrieved by an order of the Commissioner <sup>Appeal.</sup> or the assessing authority, may prefer an appeal to such authority, as may be prescribed, within a period of sixty days from the date of receipt of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) No appeal shall be entertained, unless it is accompanied by a satisfactory proof of the prior payment of not less than twenty-five per cent of the total amount of tax, penalty and interest, if any.

(3) After entertaining an appeal under sub-section (1), the appellate authority may, after giving the appellant an opportunity of being heard,—

- (a) confirm, reduce, enhance, annul or modify the assessment, interest, or penalty ; or
- (b) set aside the assessment, interest or penalty, and direct the assessing authority to pass a fresh order after such enquiry, as may be directed ; or
- (c) pass such order, as it may think fit.

(4) The appellate authority may, at the time of entertaining an appeal, allow the proprietor to produce fresh or additional evidence before it in case, it is satisfied that the proprietor was prohibited by sufficient cause to produce the same before the assessing authority and there was no wilful or unreasonable omission on his part to produce such evidence.

(5) Every order passed under sub-section (3), shall be communicated to the proprietor and the assessing authority, against whose order, the appeal was preferred and also to the Commissioner.

Revision.

**38. (1)** The Commissioner shall, by an order, have the power to revise, at any time, any order passed by the assessing authority or any officer, appointed under sub-section (1) of section 3, either *suo moto* or on an application of the proprietor submitted to him within a period of sixty days from the date of communication of the order :

Provided that the State Government may, entertain an application of the proprietor submitted after the expiry of sixty days, but not beyond sixty days after the expiry of the former, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the revision within that period.

**(2)** The State Government may, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such orders, as it may deem fit.

**(3)** Every order passed under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall be, communicated to the proprietor and the authority or officer against whose order, the revision was filed.

Rectification of mistake.

**39. (1)** With a view to rectify any mistake, apparent from the record, the assessing authority, appellate authority or revising authority, as the case may be, may, at any time, but within a period of three years from the date of the order passed by it, amend or rectify such order :

Provided that where such rectification may enhance an assessment or otherwise increase the liability of the proprietor, such order shall not be passed, unless the assessing authority, appellate authority or revising authority, as the case may be, has given a notice to the proprietor to do so, and has given him an opportunity of being heard.

**(2)** An order passed under sub-section (1), shall be deemed to be an order, passed under those provisions of this Act, under which the original order had been passed.

**(3)** Where such rectification may reduce an assessment or penalty, the assessing authority shall make the refund, which may be due to the proprietor.

**(4)** Where such rectification may enhance the amount of tax or penalty or interest or reduce the amount of refund, as the case may be, the Commissioner shall, pass an order for the recovery of the amount, due as per provisions of this Act.

40. (1) An officer, not below the rank of the Deputy Excise and Taxation Commissioner, may, in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed, either *suo moto* or on an application made to him in this behalf, by an order in writing, transfer any case or proceeding or class of proceedings from him to any other officer working under him, and in the same way, may transfer any such case, including the case, already transferred under this section, from one officer to another or to himself.

Power to transfer proceedings.

(2) Where any proceeding or class of proceedings or case is transferred under sub-section (1), the officer to whom such proceeding or class of proceedings or case is transferred, he shall proceed to dispose of as if, it had been initiated by him irrespective of the local limits of his jurisdiction, and such transfer shall not render necessary, the re-issue of any notice, already issued before such transfer; and the officer to whom the proceeding or case is transferred, may, in his discretion, continue it from the stage at which, it was left by the officer from whom it was transferred.

41. (1) Any proprietor, who is entitled or required to attend any authority in connection with any proceeding under this Act, may be represented by a person, authorised by him in writing in this behalf, being a relative or a whole time employee of the proprietor or an advocate or a tax consultant, not being disqualified by or under sub-section (2) or sub-section (3).

Proprietor permitted to attend through authorized agent.

*Explanation.*—For the purposes of this section, a “tax consultant” means,—

- (a) a retired Gazetted Officer of the Punjab Excise and Taxation Department, who has worked either as a taxing authority or an appellate authority or both for a minimum period of five years after a period of two years from the date of his retirement ; or
- (b) any person, who has passed an accountancy examination recognised by the Central Board of Direct Taxes or holds a degree in Commerce, Law, Economics, Banking, Auditing, conferred by any Indian University, incorporated by law.

(2) No person, who was dismissed from service of any Government, shall be qualified to represent any proprietor under sub-section (1).

(3) If any advocate or other person, who represents a proprietor, is found guilty of misconduct in any proceeding before any authority under this Act by the Commissioner, the Commissioner may direct that he shall be disqualified to represent the proprietor under sub-section (1) :

Provided that no such direction shall be issued in respect of any person, unless he is given a reasonable opportunity of being heard.

(4) Any person against whom any direction is issued under sub-section (3), may appeal to the State Government against such direction within a period of sixty days of its communication to him.

Delegation of powers.

42. Subject to such conditions, as may be prescribed, the Commissioner may, by an order in writing, delegate any of his powers under this Act to any officer, appointed under section 3 to assist him.

Returns etc.  
to be  
confidential.

43. (1) All particulars contained in any return furnished or accounts or documents produced in accordance with the provisions of this Act or in any evidence, given in the course of any proceeding under this Act, except in the proceeding before a court of law, shall be treated as confidential.

(2) Nothing in this section shall apply to the disclosure of any of the particulars, referred to in sub-section (1), for the purpose of any investigation or prosecution under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) in respect of such return, accounts documents or evidence, or for the purpose of departmental use of the officials of the Government of India or of any State Government, or for the purpose of any inquiry in relation to a business transaction by a person, who is a party to such transaction.

Power to seek assistance from police officer or other officer.

44. An officer, exercising the powers under this Act, may take the assistance of any police officer or other officer of the State Government, as and when required and upon such request, the police officer or the other officer, as the case may be, shall render necessary help in accordance with law.

Power to summon witness and production of records.

45. (1) In performing the functions conferred on them by or under this Act, the Commissioner or the officers, appointed under section 3 to assist him, shall have all the powers of a Civil Court under the provisions of the Civil Procedure Code, 1908 (Central Act 5 of 1908) in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation ;
- (b) compelling the production of documents and impounding them ;
- (c) proof of facts by affidavits ; and
- (d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) In the case of an affidavit, any officer, appointed under section 3, may administer the oath to the deponent.

(3) Any proceeding under this Act before the Commissioner or any officer, appointed to assist the Commissioner under section 3, shall be deemed to be a 'judicial proceeding' within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) and for the purposes of section 199 of that Code.

46. (1) No suit shall lie in any civil court to set aside or modify an assessment, made or order passed under this Act. Bar of proceedings.

(2) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer of the State Government for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

47. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the manner, in which tax is to be paid by the proprietor under sub-section (3) of section 4 and sub-section (2) of section 5;
- (b) the manner and period in which normal rates for luxuries are to be declared under section 7;
- (c) the manner for making an application for registration and prescribing fee therefor under sub-section (2) of section 8;
- (d) the manner for registering the proprietor and prescribing the form of registration certificate under sub-section (3) of section 8;
- (e) the manner for filing return and making payment of the due amount by the proprietor under the second proviso to sub-section (3) of section 8;
- (f) the manner for informing the Commissioner under section 9;

- (g) the manner for furnishing security, additional security and further security to make up for the amount, respectively, under sub-sections (1), (3) and (6) of section 12;
- (h) prescribing form for filing self assessment return under sub-section (1) of section 13;
- (i) the manner for furnishing satisfactory proof of payment of tax by the proprietor under sub-section (2) of section 13;
- (j) the manner for verification of returns under sub-section (3) of section 13;
- (k) prescribing the manner for making payment of additional amount of tax for the period of delay by the proprietor under sub-section (6) of section 13;
- (l) prescribing the form of notice of demand specifying therein the sum payable under sub-section (11) of section 14;
- (m) prescribing the manner and period in which refund is to be made to the proprietor of the amount of tax, penalty or interest under section 22;
- (n) prescribing other registers or records under section 25;
- (o) prescribing the conditions requiring a proprietor to produce records of accounts, registers or other documents or to furnish any information relating to his business to the assessing authority under sub-section (1) of section 26;
- (p) prescribing the authority to which appeal is to be preferred by a proprietor under sub-section (1) of section 37;
- (q) prescribing the manner in which and the conditions, subject to which, the assessing authority may transfer any case or proceeding or class of proceedings under sub-section (1) of section 40;
- (r) prescribing the conditions, subject to which, the Commissioner may delegate his powers to any officer under section 42; and
- (s) any other matter, which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees, that the rule should not be made, the rule shall thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment, shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

48. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order, published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it, to be necessary for removing the difficulty :

Provided that no order under this section, shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall be laid as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

49. (1) The Punjab Tax on Luxuries Ordinance, 2008 (Punjab Ordinance No. 4 of 2008), is hereby repealed.

Power to  
remove  
difficulties.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.